States/UT's	1995-96 Target	%age Achiev.	1996-97 Target	%age Achiev.	1997-98 Target	%age Achiev.	1998-99* Target	%age* Achiev.
Bihar	217292	52.70	151453	87.98	109982	94.11	171378	44.59
Goa	861	112.31	1736	26.84	548	84.49	130	331.54
Gujarat	34501	92.08	33633	90.63	20581	118.75	19692	63.19
Haryana	10846	83.20	6983	88.11	4943	91.14	10690	30.48
Himachal Pradesh	2736	63.12	2165	109.61	1572	117.24	4879	9.94
Jammu & Kashmir	10561	33.65	5347	190.71	3197	193.06	7699	54.55
Karnataka	52133	71.85	53181	85.56	37653	115.59	39505	60.96
Kerala	24624	119.27	18554	125.05	12454	103.05	17726	44.27
Madhya Pradesh	113384	110.91	147902	59.07	71054	142.92	103652	59.35
Maharashtra	89776	74.24	81120	71.80	61123	99.32	78092	25.21
Manipur	1022	76.71	808	88.49	590	185.76	1911	29.09
Meghyala	1195	17.32	946	68.29	688	45.93	2409	3.36
Mizoram	504	112.90	398	92.71	288	104.86	472	54.03
Nagaland	1281	36.69	1014	364.00	734	727.38	2050	42.73
Orissa	62986	81.02	62248	87.73	45486	109.97	67684	34.00
Punjab	7047	15.91	4966	34.41	3517	91.98	5630	30.07
Rajasthan	50875	82.08	50325	92.76	29524	118.07	35599	51.42
Sikkim	1491	71.43	369	205.96	269	219.33	784	52.30
Tamil Nadu	74205	76.66	71598	89.33	50689	110.14	46258	72.16
Tripura	1327	101.58	1051	93.53	766	217.36	4519	57.14
Uttar Pradesh	204003	77.98	241251	57.95	136645	69.18	188051	43.28
West Bengal	69579	49.26	70979	48.92	50249	87.43	74594	32.90
A and N Islands	377	5.57	337	23.15	236	2.54	202	2.97
D and N Haveli	205	6.34	278	17.99	127	78.74	309	1.62
Daman and Diu	121	51.24	120	76.67	75	50.67	10	0.00
Lakshadweep	189	5.29	0	0.00	121	49.59	17	182.35
Pondicherry	369	9.76	330	34.24	236	90.68	257	43.97
TOTAL	1147489	75.29	1123560	71.76	718326	107.78	987466	44.72

*As per latest information available.

Funds for Watershed Development Programme

1671. SHRI C. RAMCHANDRAIAH: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Watershed Development Programme is being used from 1st April, 1995, as a tool for overall economic development of rural areas;

(b) if so, what are the total funds available for this programme for various States;

(c) whether all these funds have been spent on schedule;

(d) whether any effective informaion analysis system has been put in place to support the Programme; and

(e) whether regular feedback on the progress and results of the programme has been received by the Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOWDA PATIL): (a) Yes, Sir. The Watershed Development Programme is being implemented in the Ministry of Rural Areas and Employment under the Guidelines for

Watershed Development w.e.f. 1st April, 1995. The programme is being implemented under four schemes/programmes namely: Drought Prone Areas Programme/Desert Development Programme/Employment Assurance Scheme and Integrated Wastelands Development Projects Scheme.

In addition to the above schemes/ programmes, watershed development is one of the permissible items of work allowed under Jawahar Rozgar Yojana scheme

(b) and (c) The total funds available under Integrated Wastelands Development Projects Scheme/Drought Prone Areas Programme/ Desert Development Programme and Employment Assurance Scheme during 1998-99 is Rs. 2257.10 crores.

(d) and (e) The projects/programmes are continously monitored through periodical progress reports/review meetings/inspections at the level of District Rural Development Agencies/Zilla Parishads/State Governments as well as evaluted by the independent evalutors at times.

राष्ट्रीय पेयजल मिशन

1672. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेयजल की समस्या से ग्रस्त देश के क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कायम करने के लिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई थी,

(ख) यदि हां, तो इस मिशन की स्थापना कब की गई थी और मिशन द्वारा पेयजल परियोजनाओं के निर्माण पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है, और

(ग) क्या देश के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यक व्यय राशि का कोई अनुमान लगाया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय पेयजल मिशन वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में राजीव गांधी-राष्ट्रीय पेय जल मिशन के जरिए सहयोग देती है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1998 तक ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया व्यय 9603.15 करोड़ रुपये हैं।

(ग) राज्य सरकारों ने नौंवी योजना के दौरान देश की सभी ग्रामीण बसावटों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 9149.12 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाएं

1673. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अनेक पेयजल परियोजनाएं निर्माणधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1998 तक निर्माणाधीन इन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता होने का अनुमान है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की प्रणाली की तरह त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इसीलिए निर्माणाधीन परियोजनाएं आदि जैसी जानकारी केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण बसावटों को दिसम्बर, 1998 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में 23191.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।